सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 2 SEPTEMBER TO 8 EPTEMBER 2020 • VOLUME- 6 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING | DESIGN | TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

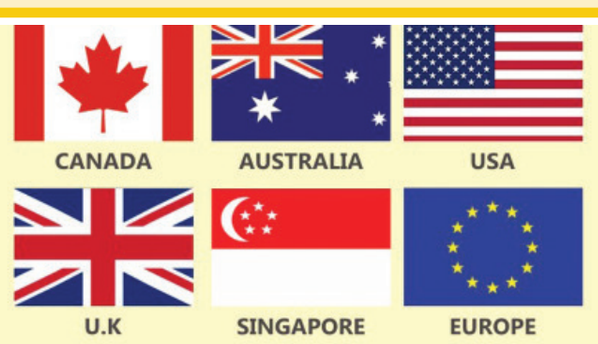

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

*T&C apply

कोविड-19 महामारी के बीच समाजों को ज्यादा तेजी से खोलना विनाशकारी होगा-डब्ल्यू.एच.ओ

■जिनेवा/ब्यूरो

विश्व स्वस्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच समाजों को इतनी जल्दी खोलना तबाही का कारण बनेगा। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गब्रेयसस ने सोमवार को जोर देकर कहा कि जो देश लॉकडाउन खोलने के प्रति गंभीर है उन्हें संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भी गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कहा, इसे संतुलित करना असंभव नहीं है। टेड्रोस ने देशों, समाजों और लोगों को चार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया, जिनमें बड़े आयोजनों से बचने, सबसे असुरक्षित लोगों की रक्षा, स्वयं की रक्षा और संक्रमितों का पता लगाने और उनके संपर्क में आए लोगों को पृथक करने के लिए पता लगाने, अलग करने, जांच करने और संक्रमित पाए जाने पर उचित देखभाल शामिल है।

डब्ल्यूएसओ प्रमुख ने कहा कि नये सर्वेक्षण में पता चला है कि इसमें शामिल 90 प्रतिशत देशों में कोविड-19 की वजह से अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं। उल्लेखनीय है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कोविड-19 के असर का आकलन करने के लिए 105 देशों में यह सर्वेक्षण किया गया था।

टेड्रोस ने कहा कि मार्च और जून में पांच क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि मौजूदा महामारी की तरह स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत है। सर्वेक्षण से पता चला कि 70 प्रतिशत देशों में नियमित टीकाकरण सबसे अधिक प्रभावित हुआ

इसके बाद जांच और गैर संचारी रोगों जैसे हृदय रोग आदि का इलाज प्रभावित हुआ. करीब एक चौथाई देशों ने कहा कि महामारी की वजह से आपात चिकित्सा सेवा प्रभावित हुई है।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गईं।

उन्होंने ट्वीट किया, '' जीडीपी -23.9 प्रतिशत हो गई. देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी। उन्होंने ट्वीट किया, ''आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी. कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ. लेकिन आज हालत देखिए. जीडीपी -23.9 प्रतिशत तक गिर गई। बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया।''

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''मोदी जी, अब तो मान लीजिए कि जिसे आपने ''मास्टरस्ट्रोक'' कहा, वास्तव में वो ''डिजास्टर स्ट्रोक'' थे। नोटबंदी, ग़लत जीएसटी, और देशबंदी (तालाबंदी).'' गौरतलब है कि कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट आयी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े सोमवार को जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट दिखी है। सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

ड्रैगन ने चली नई चाल

कैलास मानसरोवर इलाके में बनाई मिसाइल साइट

■ लद्दाख/ब्यूरो

भारत-चीन के बीच तनातनी बातचीत के बावजूद कम नहीं हो रही है। हाल ही में 29-30 अगस्त की रात को चीन की पीएलए लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था जिसे भारतीय सेना के जवानों ने विफल कर दिया। इस घटनाक्रम के बावजूद चीन अपने नापाक इरादे जाहिर करता रहा है। अब चीन भारत से लगी सीमा पर हवाई किलेबंदी को मजबूत करने में जुटा हुआ है। जिसका खुलासा हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि चीन ने कैलास मानसरोवर पर मिसाइल साइट तैयार की है।

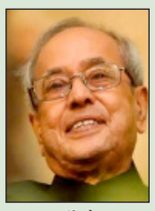

जहां पर उसने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। माना जा रहा है कि जब से भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुआ है तब से चीन डरा हुआ है। ऐसे में वह लगातार अपनी हवाई सीमा को मजबूत बनाने के लिए तरह-तरह की चाल चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कैलास मानसरोवर के इलाके में न सिर्फ अपनी तैनाती बढ़ाई है। बल्कि उसने एक मिसाइल साइट का भी निर्माण कर लिया है। विशषज्ञों का मानना है कि चीन की लगातार उकसावे की रणनीति रही है। जो यह दिखाती है कि वह सीमा पर शांति नहीं चाहता है।

बता दें कि चीन के इस कदम से भारत के साथ उसके संबंध सीमा पर और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि, पहले की यथास्थित बहाल करने के लिए कई दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है।

चीन ने कैलास मानसरोवर के पास में जो मिसाइल साइट बनाई है वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से करीब 100 किमी की दूरी पर है और यदि चीन यहां से हमला करना चाहे तो भारतीय सीमा पर कुछ सेकंड के अंदर ही मिसाइल दाग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में रक्षा क्षेत्र विषय के प्रोफेसर गिरीशकांत पांडेय ने एपोक टाइम्स को जानकारी दी कि कैलास-मानसरोवर के पास चीन ने मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल डीएफ-21 तैनात की है। जिसकी मारक क्षमता 2,220 किमी तक है। ऐसे में इस मिसाइल के दायरे में उत्तर भारत के कई प्रमुख शहर आते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रहकर प्रणब दा को दी श्रद्धांजलि, कहा- देश ने एक विशिष्ट नेता खो दिया

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मंगलवार को शोक प्रकट किया और कहा कि देश ने एक विशिष्ट नेता एवं उत्कृष्ट सांसद को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रखकर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव में कहा, ''मंत्रिमंडल भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश ने एक विशिष्ट नेता एवं उत्कृष्ट सांसद को खो दिया।'' मंत्रिमंडल ने कहा कि भारत के 13वें राष्ट्रपति मुखर्जी का प्रशासन में अतुलनीय अनुभव था जिन्होंने विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में देश की सेवा की।प्रस्ताव के अनुसार, '' केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं की गहराई से सराहना करता है तथा सरकार एवं सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है ''

क्या और अधिक स्पैशल ट्रेनें चलने की है संभावना ? रेल मंत्रालय ने दिया यह जवाब

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

रेलवे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में यात्रियों का आवागमन सुगम करने के लिए और अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है जिसके लिए राज्य सरकारों से सहमति मांगी जा रही है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने हालांकि, यह नहीं बताया कि वर्तमान में चल रहीं 230 स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त ऐसी कितनी और ट्रेन चलाई जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि नयी स्पेशल ट्रेन चलाने संबंधी घोषणा आगामी कुछ दिन में की जाएगी। वर्तमान में कोविड-19 की वजह से सभी नियमित यात्री सेवाएं निलंबित हैं। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि और अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। हालांकि, अभी यह नहीं स्पष्ट हो पाया है कि कितनी और ट्रेनें चलाई जाएंगी

जालंधर ब्रीज में प्रकाशित खबर का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाईवे ने लिया कड़ा संज्ञान

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

पिछले कई अंकों में जालंधर ब्रीज द्वारा हाईवे में की गयी त्रुटियों को जनता के सामने उजागर किया गया जिस पर विभाग को तुरंत एक्शन लेकर उसको ठीक करवाना पड़ा उसी विस्तार में पिछले अंक में फगवाड़ा-रोपड़ हाईवे पर टोल के नजदीक आवारा पशुओं की समस्या को उजागर किया था और स्थानीय प्रशासन को कुम्भकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया था जिस पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बलाचौर को पत्र लिख कर जालंधर ब्रीज की खबर का हवाला देते हुए इसे तुरंत हल करने के लिए लिखा और भविष्य में कोई जानमाल का नुक्सान ना हो सके इसके लिए अपनी पेट्रोलिंग टीम को भी चेताया।

जालंधर ब्रीज के पिछले अंक में प्रकाशित की गयी खबर।

लोग दबे हुए है कोरोना के बोझ में पुडा का मंत्री अपनी ही मौज में

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जनता को संबोधित करते हुए बड़े-बड़े दावे करते है की उनकी सरकार अपने किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और साथ ही अपने लाइव संबोधन के दौरान कोरोना महामारी को लेकर भी बड़ी चिंता प्रकट करते हुए अक्सर लोग उनको टीवी पर देखते है परन्तु ग्राउंड जीरो पर लोग इनसे पूरी तरह खफा है क्यूंकि लोगों का कहना है की अगर वो कोरोना से बच भी गए तो भूखमरी से मर जायेंगे। इसका कारण सरकार द्वारा बिना सोचे समझे हर रोज़ नए-नए कानून बनाना और फिर उसको डंडे के जोर पर लागू करवाना लोग मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे है की कोरोना तो मार्च से प्रभाव में आया परन्तु कोरोना रूपी भ्रष्ट अफसर लोगों का खून चूस रहे है वो कौन सी प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होगी जिसमे उनके खासमखास मंत्री भी लगाम लगाने में नाकाम है सूत्र बताते है की पुडा का मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वफादार सिपाहिओं में से एक है जिसको अपने पुराने दुश्मन को मात देने के लिए 2019 के शहरी हल्कों में चुनावी हार का ठीकरा उसके सिर फोड़ कर एक वफादार से पुडा जैसे गंभीर विभाग को छीना और दूसरे वफादार को नवाज़ा। परन्तु इसका फायदा सिर्फ मुख्यमंत्री को ही हुआ लगता है लोग तो आज भी इस मुखौटी बदलाव से दुखी है क्यूंकि मंत्री की नीचे से लेकर ऊपर तक कोई सुनता ही नहीं है उसका मुख्य कारण निचले स्तर पर चाहे अमृतसर हो जालंधर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन सभी पर अकाली दल के बड़े नेता के करीबी अफसर ही विराजमान है और इस बात को और बल तब मिल गया जब मंत्री ने सरकारी पर्सनल असिस्टेंट भी वहीं अपने साथ रखा हुआ है जिसने माझे के कदावर नेता के साथ सरकारी तौर पर एक तरह से हल्का इंचार्ज के रूप में कांग्रेसियों में दहशत बना के रखी थी और किसी की भी वो परवाह नहीं करता था। आज भी हाल उसका वहीं है मंत्री बदल गया पर साब की मनमर्जी बदली नहीं अब तो लोगों को और कांग्रेसी वर्करो को पुरा विश्वास होने लग गया है की सरकार अकाली दल ही चला रहा है क्यूंकि मंत्री ने कभी किसी भी लोगों की तकलीफों को अखबार के माध्यम से प्रकाशित किये हुए जनहित मुद्दे पर संजीदगी नहीं दिखाई क्यूंकि वो सेक्टर 16 के नजदीक स्थित चंडीगढ़ कोठी जिसका सारा बोझ आम जनता उठाती है उसमें आपको जनता से कम और मोहाली- चंडीगढ़ के बड़े बिल्डर्स और उद्योगपतिओं को मिलने में व्यस्त रहते है या वही आराम करते हुए ज्यादा पाए जाते है जो की इस कोरोना महामारी में सरकार के लिए किसी को ना विरोध करने देना या किसी को ना मिलना पड़े पूरे राज्य में धारा 144 लगा रखी है और वो भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए या राज्य के अन्य दलों के लिए परन्तु अकाली दल भाजपा के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है अगर जल्द ही पुडा का मंत्री कुंभकर्णी नींद से न जागा तो स्कालरशिप घोटाले की तरह रेगुलारिसेशन के नाम पर एकत्रित की हुई धनराशि का घोटाला भी जल्दी उजागर हो जायेगा क्यूंकि ग्राउंड जीरो पर किसी भी कॉलोनी में कोई डेवलपमेंट विभाग के भ्रष्ट अफसरों द्वारा नहीं की गई जनता अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और यह सरकारी पी.ए. जल्द ही 2022 में अपने पुराने वज़ीर के पास देखा जाएगा।

अवैध कालोनियों में राजीनामा योग्य निर्माण के गलत रेट लगाकर लोगों को किया जा रहा गुमराह

पुडा विभाग

जालंधर ब्रीज ब्यूरो

केन्द्र में प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की जिसको पंजाब की सरकार पहले से ही बखूबी से निभा रही थी और कोरोना महामारी के बाद और तेज़ी से निभा रही यह कोई काल्पनिक व्यंग्य नहीं इसकी हकीकत आप जब गहराई से जांच करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा।

पूर्व अकाली भाजपा सरकार द्वारा 2013 में पंजाब में चल रहे लैंड माफिया द्वारा काटी गयी कोलोनियों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित उन कोलोनियों के निवासियों को राहत प्रधान करते हुए सभी कोलोनियों और प्लाटों को नियमित कराने के लिए एक मौका दिया और लोगों ने पूरी जिम्मेवारी के साथ सरकार द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार में उनके क्षेत्र फल के हिसाब से बनती धनराशि जमा करवाई और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया और जिन्होंने 2013 में इस योजना का लाभ नहीं लिया।

अभी की मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने दोबारा पालिसी को लाकर अवसर दिया परन्तु सरकार ने लोगों से तो बनती राशि की वसूली कर ली लेकिन उसके मुलभुत सुविधाएं देने के वादे को भूल गयी और जो 5 प्रतिशत ज्यादा बिल्डिंग की कवरेज को राजीनामा का रेट उनके अफसर पालिसी से नहीं अपनी मर्जी से अपने द्वारा काटी गयी कोलोनियों के रेट पर जैसे की अर्बन एस्टेट के रेट पर उनको अवैध रूप से नोटिस भेज रही है।

यह एक गंभीर जांच का विषय है की जो करोड़ों रुपया सरकार ने वसूली की उसको कहाँ खर्च किया जो अब फिर अवैध रूप से लोगों की राजीनामा योग उसारी के गलत रेट को लगाकर क्यों आम जनता को इस कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में और सताया जा रहा है।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन, राष्ट्र ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे अभिजीत बनर्जी ने मुखाग्नि दी। प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि लोधी रोड स्थित श्मशान घाट में दी गई।बता दें कि अंतिम संस्कार कोरोना महामारी के जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया। इस दौरान परिवार और रिश्तेदार पीपीई किट पहनकर मौजूद रहे। सेना की टुकड़ी ने पूर्व राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी। इससे पहले प्रणब मुखर्जी को 10 राजाजी मार्ग स्थित घर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी थी।

दखल

कृषि नीतियां और विकास

केंद्र और राज्य सरकारें कृषि को घाटे वाला क्षेत्र कह कर उसे उबारने की बात तो करती हैं, लेकिन कृषि घाटे में क्यों बनी रहती है? किसानों की माली हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? किसानों की दी जाने वाली सुविधाएं क्या किसानों के लिए मुफीद हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें जब तक कृषि के प्रति सकारात्मक और व्यावहारिक नीति नहीं बनातीं, तब तक, कृषि और कृषक को डूबने से बचाया नहीं जा सकता।

इस साल रबी की लाखों एकड़ फसल बेमौसम बरसात के कारण बर्बाद हो गई। मार्च में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में घनघोर आंधी-तूफान और ओले पड़े। इससे गेंहू, जौ, सरसों, अलसी, अरहर, मटर, आलू और सब्जियों की लाखों एकड़ जमीन में लहलहातीं फसलें जमीन पर लोटने या पानी में डूब कर सड़ने लगीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को जायजा लेने और उसके मुताबिक किसानों को राहत देने की बात कही है। कुदरत किसानों पर आए दिन कहर ढाती रहती है। सरकारें तुरंत राहत देकर मरहम लगाने की कोशिश करती हैं। यह एक रिवाज की तरह आजादी के बाद से निभाया जा रहा है। इससे किसानों को फौरी तौर पर कुछ राहत तो मिल जाती है, लेकिन उनकी मूल समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। आजादी के बाद से अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई, जिसने खेती-किसानी को सबसे कठिन और अनिश्चित धंधे से निकाल कर सरल और निश्चित आय का बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया हो। सरकारों की नीतियों में किसानों को लालीपॉप थमाने के अलावा कोई ठोस नीति या योजना नहीं रही। इसलिए समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं।

भारत सहित दुनिया के सभी देशों की नीतियां खेती-किसानी के प्रति नकारात्मक रही हैं। मौजूदा विकास का मॉडल सुख-सुविधाओं से संपन्न शहर पर आधारित है। गांवों को विकसित करके उन्हें पूर्ण सक्षम बनाने की योजना, भारतीय कृषि नीति का हिस्सा कभी नहीं रही। गौरतलब है कि आजादी के पहले भारत का किसान गांव छोड़ कर शहरों की ओर पलायन करने की कभी नहीं सोचता था। कुदरत की मार और विदेशी शासन की किसान-विरोधी नीतियों के कारण भी किसान अपना पुस्तैनी गांव और एकमात्र परिवार का सहारा खेती छोड़ने के लिए नहीं सोचता था। ऐसा क्या हो गया कि आजादी के बाद किसान धीरे-धीरे अपना पुस्तैनी काम-धंधा छोड़ शहर-कस्बों की ओर रुख करने लगा? शायद केंद्र और राज्य सराकारों ने कभी इस बारे में संजीदगी से सोचा ही नहीं।

विकसित देशों में कृषि वहां की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग नहीं है, इसलिए वहां कृषि और किसानी उनकी योजनाओं में कोई खास महत्व नहीं रखते। इसके बावजूद विकसित देशों के किसानों को वहां की सरकारें जो सुविधाएं, राहत, छूट और मदद देती हैं, उससे वहां का किसान अमन-चैन और सम्मान की जिंदगी जीता है। इसलिए कुदरत का कहर या अन्य समस्याओं की वजह से वहां का किसान आत्महत्या नहीं करता और न ही अनिश्चिय के भंवर में डूबता-उतराता है। पर वैश्विक स्तर पर कृषि की जो नीतियां चल रही हैं, वे किसानों के लिए किसी भी तरह फायदेमंद और राहत देने वाली नहीं हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार कह रही है कि उसकी नीति पिछली सरकारों से बेहतर और किसानों को खुशहाली देने वाली है। अगर ऐसा है, तो गांव छोड़ कर अच्छी सुख-सुविधाओं और बेहतर आमदनी की आस में शहर आए लोग अपने गांव लौट क्यों नहीं रहे हैं? जबकि पिछले 72 वर्षों में खाद्यान्न उत्पाद बढ़ा है और केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से विविधता लाने के मकसद से फसल की किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इससे जहां फसलों में पोषण की मात्रा बढ़ी, वहीं उनमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी ओर, मोनसेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बुला कर भारतीय कृषि और किसानों को बर्बाद करने के कदम विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत उठाए गए।

मोनसेंटो के बीज परंपरागत बीजों से अधिक पैदावार तो देते हैं, पर वे अगली बार बोने के लिए बेहतर नहीं होते और उससे जमीन के बंजर होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इससे किसान दोहरी मार का शिकार हुआ। एक तो वह मोनसेंटो के बीज बोकर अपने खेतों की उर्वरा-शक्ति गंवा बैठा, वहीं परंपरागत बीजों के अनुकूल उसकी जमीन नहीं रह गई। बिजली, पानी, खाद, उत्पाद का उचित दाम न मिलने, बिचौलियों के जरिए ठगे जाने और मंहगाई की मार जैसी समस्याएं किसानों को खेती छोड़ कर शहर की ओर पलायन करने पर मजबूर करती रही हैं। वैश्विक स्तर पर विकास का मॉडल ही किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर करता है। गौरतलब है कि विकास के वैश्विक मॉडल को ही पिछले 72 सालों से सरकारें अपनाई हुई हैं। यह मॉडल किसानों को खेती से बेदखल कर उन्हें शहरों के लिए दिहाड़ी मजदूर बनाने वाला है।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते थे कि देश प्रगति के रास्ते पर तब तेजी से बढ़ेगा जब 2022 तक कम से कम 38 प्रतिशत किसानों को खेती से बेदखल कर शहरों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में लाया जाए, क्योंकि शहरों में दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत है। भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश की रही है। यहां की संस्कृति, भाषा, भाव, रीति-रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं कहीं न कहीं कृषि से सीधे जुड़ते हैं। पर आजादी के बाद कृषि की जगह उद्योग-धंधों को हर तरह से प्रोत्साहित किया गया और किसानी और किसान को हर तरह से हतोत्साहित। इसी का परिणाम है कि अब लाखों की तादाद में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। नेशनल स्कीम पॉलसी कहती है कि कृषि से देश की अर्थव्यवस्था को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिनसे अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिले। आमतौर पर यह बात ठीक कही जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र से आमदनी कम हो या बहुत कम हो, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन गहराई से चिंतन करने से इस बात में कोई दम नजर नहीं आता।

साल 1970 में गेंहू का दाम 75 रुपए प्रति कुंतल था और 2015 में इसका दाम 1450 रुपए के आसपास था। इन 45 सालों के दौरान सरकारी नौकरी-पेशा लोगों के वेतन में 120-150 गुने की वृद्धि हुई। जबकि किसान की आमदनी में महज 19 गुने की वृद्धि हुई। सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य भत्ता चार लाख 80 हजार रुपए मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, जजों, कर्मचारियों को 21 हजार रुपए अतिरिक्त भत्ता मिलता है। लेकिन किसानों के लिए न कोई भत्ता है, न कोई योजना, जिससे वे भी बिना तनाव के जी सकें। अरबों रुपए पूंजीपतियों को बैंक दे देते हैं और न लौटाने पर उनकी न तो कुर्की होती है और न उन्हें परेशान किया जाता है। पर किसान को दस-बीस हजार के ऋण के लिए परेशान किया जाता है और उनके खेत, घरेलू सामान और मकान की कुर्की तक होती है। सवाल है कि जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उसी के साथ ऐसा दोहरा और गैरइंसानी व्यवहार क्यों? क्या किसान ईमानदारी के साथ कठिन मेहनत करके देश को अन्न नहीं खिलाता?

सरकारें कृषि को घाटे वाला क्षेत्र कह कर उसे उबारने की बात तो करती हैं, लेकिन कृषि घाटे में क्यों बनी रहती है? किसानों की दी जाने वाली सुविधाएं क्या किसानों के लिए मुफीद हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि घाटे वाली खेती की सबसे बड़ी वजह किसान से ताल्लुक रखने वाली नीतियां, उसके साथ दोहरा बर्ताव, उसकी उपेक्षा और खेती-किसानी को सबसे निम्न स्तर का मान कर उसके लिए कोई ठोस योजना न बनाना है। कृषि लागत और कृषि-उत्पाद के दाम में अंतर को भी समझने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें जब तक कृषि के प्रति सकारात्मक और व्यावहारिक नीति नहीं बनातीं, तब तक, कृषि और कृषक को डूबने से बचाया नहीं जा सकता। अगर सरकारें वाकई किसानों के प्रति चिंतित हैं तो उन्हें ऐसी नीति बनानी होगी जो अन्नदाता को फसल का वाजिब दाम दिलाने की गारंटी दे।

विचार

चीन का स्थाई इलाज जरूरी

गलवान में हिंसक झड़प के बाद अब चीन ने पेंगोंग के पास बदमाशी की है। पता चला है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। 29 अगस्त की रात यह झड़प पेंगोंग त्सो झील के पास हुई है। इस घटना से साफ है चीन का स्थाई इलाज करना होगा।

चीन के साथ सीमा विवाद निपटाने को लेकर भारत गंभीर है। वह हर जतन कर रहा है। न चाहते हुए भी सैन्य स्तर की पांच बार बातचीत भी कर चुका है। सीमा पर चीन की हर चालबाजी को जानते हुए भी चुप है। वह इसलिए क्योंकि भारत की मंशा एलएसी पर शांति बनाए रखने की है। मगर चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद अब उसने पेंगोंग झील के पास बदमाशी की है। पता चला है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। 29 अगस्त की रात यह झड़प पेंगोंग त्सो झील के पास हुई है। सरकार ने कहा है कि हमारे जांबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। चीन 500 सैनिकों संग घुसपैठ करना चाहता था।

सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने कहा कि पीएलए के जवानों ने 29/30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुई सैन्य और राजनयिक बातचीत का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। इससे पहले भारत और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इस झड़प में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार बात चल रही है, इसके बावजदू चीन अपनी आदत से बाज नहीं आया और 29 अगस्त की रात को फिर तयशुदा सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की। चीन ने जिस इलाके पर अतिक्रमण करने का विफल प्रयास किया। वहां भारत ने 1990 के दशक के अंत में वार्ता के दौरान अपना दावा किया था। तब चीनी सेना ने यहां एक सड़क निर्माण कर कहा था कि यह अक्साई चीन का हिस्सा है जो उसके नियंत्रण में है।

पेंगोंग झील या पेंगोंग त्सो लद्दाख में भारत-चीन सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी है और लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। ताजा घटना से चीन की चाल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। चीन की इस तरह की हरकत सिर्फ भारत को पीछे हटाने के लिए की है। वह कभी मिसाइल तो कभी दूसरे अस्त्रों के बहाने भारत पर दबाव बनाने की मंशा रखता है कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो वह किसी भी स्तर पर जा सकता है। मगर इस बार चीन की यह घुड़की काम नहीं आ रही है। भारत ने भी मोर्चा संभाल लिया है और चीन के पीछे हटने तक भारत के कदम वापस होंगे, यह सोचा भी नहीं जा सकता। विवाद खड़े करना चीन की फितरत है। मगर इस बार उसने गलत पंगा ले लिया है। चीन समझ रहा था कि वह भारत को दबाव में ले आएगा, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा।

कई रहस्य खोलेगा सुशांत केस

सुशांत की मौत अब भी रहस्य के परदों में है, पर फिल्मी परदे की दुनिया का सच इसके जरिए एक-एक कर सामने आ रहा है। इसमें की गई साजिशें, काम देने के मामले में भाई-भतीजावाद, शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए की जाने वाली तिकड़मों आदि की परतें उघड़ रही हैं। मामले की जांच अब सीबीआई के पास है। उसकी जांच आगे बढ़ रही है। सच का पता पूरे देश को जल्द लग जाएगा।

जब से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की है, इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने शुरू हो गए हैं। पहले कहा गया कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, फिर सवाल उठे और शक भी जाहिर किया जाने लगा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर उनके साथ रह रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों से लगातार पूछताछ चल रही है। इसी पूछताछ और जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत मादक पदार्थ यानी ड्रग्स लेते थे। जबकि सुशांत के परिजनों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ही जहरीले मादक पदार्थ उन्हें चोरी-चुपके दिया करती थी। सीबीआई को रिया के वाट्सएप संदेशों से पता चला है कि उनके कुछ मादक पदार्थ विक्रेताओं से संपर्क थे। अब मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी दिल्ली से मुंबई पहुंच गए हैं। शक है कि रिया चक्रवर्ती के मुंबई के ड्रग माफिया से संबंध हो सकते हैं। यह भी संदेह जताया जाने लगा है कि सुशांत राजपूत की मौत मादक पदार्थ लेने से हुई हो सकती है।

यह असलियत तो सीबीआई जांच से सामने आएगी कि सुशांत खुद मादक पदार्थ के आदी थे या उन्हें धोखे से दिया जाता था। पर यह स्पष्ट है कि मुंबई में मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों का तंत्र सक्रिय है। जबसे सुशांत मामले में मादक पदार्थ का कोण सामने आया है, तबसे महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं को सरकार पर हमला बोलने का भी मौका मिल गया है कि महाराष्ट्र सरकार कैसे मादक पदार्थों की बिक्री रोकने में नाकाम रही है। मुंबई पुलिस को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी। अब अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी बयान दिया है कि जलसों में उन्हें पेय पदार्थ में ड्रग मिला कर दिया जाता था। यह छिपी बात नहीं है कि मुंबई की फिल्मी दुनिया में मादक पदार्थों का चलन बड़े पैमाने पर है। इस उद्योग से जुड़े लोगों पर काम का दबाव अधिक होने के अलावा कई पर अपने करिअर को लेकर तनाव भी रहता है, इसलिए उनमें मादक पदार्थों की तरफ झुकाव देखा जाता है।

पर सवाल है कि जब मादक पदार्थों को सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है और उनकी खरीद-बिक्री को लेकर कड़े कानून हैं, तो फिर किस तरह वहां ड्रग का कारोबार चलाने वालों का तंत्र सक्रिय बना हुआ है। सुशांत की मौत अब भी रहस्य के परदों में है, पर फिल्मी परदे की दुनिया का सच इसके जरिए एक-एक कर सामने आ रहा है। इसमें की गई साजिशें, काम देने के मामले में भाई-भतीजावाद, शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए की जाने वाली तिकड़मों आदि की परतें उघड़ रही हैं। यानी फिल्मी दुनिया का अंदरूनी पक्ष उतना उजला नहीं है, जितना परदे पर दिखाई देता है। जिस तरह सुशांत मामले में फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने मौन साधे रखा उससे भी उन सबकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और मानवीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छी बात है कि सीबीआई जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जल्दी सुलझता दिख रहा है। पर इसमें फिल्मी दुनिया के भीतर की जो कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर होंगी, वह शायद फिल्म प्रेमियों के मन पर अच्छा प्रभाव कतई नहीं छोड़ेंगी। मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के इस जांच से जुड़ने के बाद यह उम्मीद बनी है कि इस धंधे में लगे लोगों पर शिकंजा कसने के उपाय भी जुटाए जा सकेंगे, क्योंकि यह समस्या पूरे देश के लिए नासूर बनती जा रही है।

फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला शुरू से जिन परतों में उलझा दिखा, उसमें हर पहलू से बारीक जांच ही उसे सुलझा सकती है। इसलिए उनकी आत्महत्या और उससे जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों के मद्देनजर इसकी जांच महाराष्ट्र की पुलिस के बजाय सीबीआई से कराने की मांग उठ रही थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पुलिस की जांच पर भरोसा करना बेहतर समझा था। लेकिन जब पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई व सीबीआई जांच की मांग की, तब बिहार सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी। अफसोस की बात यह है कि इस मसले पर जहां महाराष्ट्र और बिहार की सरकार और पुलिस को मिल कर मामले सुलझाने की ओर बढ़ना चाहिए था, वहां शायद इसे अहं और टकराव का सवाल बना लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आखिर अदालत ने फैसले में समूचे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। इससे एक तरह से बिहार सरकार के रुख की पुष्टि हुई है।

हैरानी की बात तो यह है कि जिस मामले में संबंधित राज्यों की पुलिस और तंत्र को अपनी ओर से रुचि लेकर ड्यूटी के तहत जांच को पारदर्शी तरीके से कराने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसमें अघोषित रूप से कई पक्ष बन गए और उनके बीच आपस में खींचतान चलने लगी। जहां महाराष्ट्र सरकार इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं समझ रही थी, तो वहीं बिहार सरकार का रुख इससे उलट सामने आया। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें इस मामले में जितना अधिक संभव हो सके, सीबीआई जांच में सहयोग करें, ताकि इससे जुड़ी सारी परतों का खुलासा हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद इसे अलग-अलग पक्षों की ओर से जिस तरह अपनी मांग या फिर न्याय की जीत के तौर पर पेश करने की होड़ मच गई, उसे अपरिपक्व प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। जबकि फिलहाल जरूरत इस बात की है कि सीबीआई जांच को अब निर्बाध तरीके अंजाम तक पहुंचने दिया जाए, संबंधित पक्ष में इसमें सहयोग करें और जांच के निष्कर्षों का इंतजार किया जाए।

अफसोस की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से अब तक मामले में बॉलीवुड से लेकर राजनीति की दुनिया में जितने ध्रुव खड़े हो गए और उनके बीच जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप सामने आए, वे मामले की हकीकत को सामने लाने में मददगार नहीं थे। बल्कि ऐसे में आरोप और संदेह की नई परतें बन गईं, जिससे लोगों को अपनी सुविधा के मुताबिक धारणाएं बनाने का मौका मिला। यहां तक कि इस मामले को कुछ राजनीतिकों ने अपनी सुविधा का मुद्दा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ इस रास्ते दिलाया जा सकेगा? बॉलीवुड में जिस तरह से वंशवाद या फिर परिवारवाद का बोलबाला रहा है, उसमें नए कलाकारों को अपनी जगह बनाने के लिए किस तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ता है, यह छिपा नहीं है। प्रतिद्वंद्विता, खींचतान और नाकामी से लेकर चकाचौंध के बीच अकेले पड़ जाने और अवसाद से घिर जाने के हालात भी उन कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती होती है।

इसके अलावा, किसी की मौत में साजिश और रहस्य की क्या भूमिका है, यह बिना बारीक जांच के सामने आना संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कोई पूर्वधारणा बनाने के बजाय अब सीबीआई की जांच के नतीजों और फिर इससे जुड़े मुकदमे में अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। सुशांत सिंह का मामला अब एक परिवार तक सीमित नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस केस से खुद को जोड़ लिया है और न्याय की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और हर संदेही से पूछताछ कर रही है। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

ट्विटर

एलएसी पर चीन को पीछे हटना होगा। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वह नहीं माना तो दूसरे विकल्प मौजूद हैं। सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

लद्दाख में चीन की ताजा हरकत यह साबित करने के लिए काफी है कि वह बात से मानने वाला नहीं है। इसलिए अब भारत भी बातचीत में समय न गंवाए।

कमर आगा, रक्षा विशेषज्ञ

सत्यार्थ

दीर्घकालीन लाभ की सोचें

एक बकरी के सारे शरीर पर नर्म-मुलायम लंबे बाल थे। वह खुद को बहुत होशियार समझती थी। एक दिन वह घास चर रही थी, तभी शिकारी वहां आ पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर बकरी पर पड़ी, वे उसे पाने के लिए लालायित हो उठे। शिकारियों का इरादा भांपकर बकरी जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते-भागते वह एक ऐसी जगह पहुंची, जहां नर्म पत्तों वाली कुछ घनी झाड़ियां लगी हुई थीं। बकरी उनके पीछे जाकर छिप गई। थोड़ी देर में शिकारी भी पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचे, लेकिन वे झाड़ियों के कारण बकरी को देख नहीं पा रहे थे। इधर-उधर खोजने के बाद वे आगे बढ़ गए। यह देख बकरी अपनी चतुराई पर बहुत खुश हुई। कुछ देर पहले तक डर की वजह से उसका ध्यान झाड़ियों की बेलों के नर्म पत्तों की ओर गया ही नहीं था और अब जब डर जाता रहा, तो उसने तेजी से उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने काफी सारी झाड़ी चट कर डाली कि तभी शिकारी भी उसे खोजते हुए वापस उसी जगह आ पहुंचे। उन्होंने घेरकर बकरी को पकड़ लिया। वे उसे अपने साथ ले जाते हुए बात कर रहे थे कि यदि बकरी ने झाड़ियां साफ न कर दी होतीं, तो शायद वह उनकी पकड़ में ही नहीं आती। यह सुनकर बकरी को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने खुद अपने हाथों से अपना आश्रय मिटा दिया। इसी प्रकार सफलता के नशे में कई बार प्राणी अपने आश्रयदाता को छोटा समझ उसकी उपेक्षा करने या उसे नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते। जो लोग इस तरह की चतुराई दिखाते हैं, वे अपने जीवन में कभी-कभी बड़ा धोखा खा जाते हैं। समझदारी तो इसी में है कि फौरी लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालीन लाभ की सोच हो।

बेहद शानदार रहा है प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया है। उन्होंने 84 वर्ष की उम्र में आरआर आर्मी अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। वह 2012 में भारत के तेरहवें राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसदीय कैरियर करीब पांच दशक पुराना

प्रणब मुखर्जी का संसदीय कैरियर करीब पांच दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वे सन् 1982 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में, यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। उनका कार्यकाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ऋण की 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा।

राजीव गांधी समर्थकों के षडयंत्र का शिकार बने

वित्त मंत्री के रूप में प्रणव के कार्यकाल के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया।

राव ने किया राजनीतिक करियर पुनर्जीवित

प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा, जब पीवी नरसिंह राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया।

स्मृति शेष

कांग्रेसी होते हुए भी भाजपा के इन दो प्रधानमंत्रियों से थे खासा प्रभावित

देश के 13वें राष्ट्रपति मुखर्जी का पूरा राजनीतिक जीवन भले ही कांग्रेस के साथ बीता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं से वह खासा प्रभावित थे। ये दो नेता हैं पूर्व प्रधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी। इसका जिक्र उन्होंने खुद एक कार्यक्रम में किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को मुखर्जी सबसे असरदार प्रधानमंत्री मानते थे तो नरेंद्र मोदी के बारे मे उनकी राय तेजी से सीखने वाले प्रधानमंत्री की थी। मोदी खुद कह चुके हैं कि जब वह दिल्ली आए थे तो प्रणब दा ने ही उन्हें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था। राष्ट्रपति के रूप में जब मुखर्जी का अंतिम दिन था तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा था कि आपके साथ काम करना सम्मान की बात रही।

तीन बार प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए थे प्रणब दा

भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में उन चुनिंदा लोगों में से एक थे, जिनका नाम विरोधी भी सम्मान से लेते थे। हर राजनीतिक व्यक्ति की तरह प्रणब मुखर्जी की भी कई महत्वाकांक्षाएं थीं। इन्हें व्यक्त करने में वे कभी झिझके नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी हमेशा खुलकर सामने रखा। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक सफर में तीन बार ऐसे मौके आए जब लगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर तीनों बार ऐसा नहीं हो पाया। आज हम आपको बताएंगे उन तीनों मौकों के बारे में जब प्रणब दा पीएम बनते-बनते रह गए।

साल 1969 : इंदिरा कैबिनेट में नंबर दो

साल 1969 में प्रणब मुखर्जी राज्यसभा से पहली बार संसद पहुंचे। इंदिरा गांधी प्रणब दा की राजनीतिक मुद्दों की समझ की कायल थीं। इसी वजह से प्रणब दा को कैबिनेट में नंबर दो का दर्जा दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब के नाम पर चर्चा अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी हुई। मगर पार्टी ने राजीव गांधी को चुना। दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 414 सीटों के साथ सत्ता में आई। मगर प्रणब दा को कैबिनेट में जगह नहीं मिली।

1986 में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन

इस बात से नाराज होकर प्रणब दा ने साल 1986 में बंगाल में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। 1989 में राजीव गांधी और उनके बीच समझौता हुआ और समाजवादी कांग्रेस का विलय कांग्रेस में हो गया।

1991 : फिर हाथ से निकला मौका

1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए। कांग्रेस फिर सत्ता में आई। इस बार प्रणब मुखर्जी को फिर पीएम पद का दावेदार माना जा रहा था। उनके अलावा कोई दावेदारी में नहीं था। मगर इस बार भी मौका हाथ से निकल गया। इस बार नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रणब दा को पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष और फिर विदेश मंत्री बनाए गए।

2004 : प्रणब की जगह मनमोहन बने पीएम

साल 2004 में कांग्रेस में 145 सीटें और भाजपा को 138 सीटें मिलीं। अब कांग्रेस सरकार बनाने क्षेत्रीय दलों पर निर्भर थी। सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया। भाजपा ने इसका विरोध किया। तब प्रणब दा का नाम फिर चर्चा में आया, किंतु सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना।

मुखर्जी के बारे में कुछ रोचक बातें

नंबर 13 से अजब रिश्ता: प्रणब मुखर्जी का 13 से अनोखा नाता रहा है। वे 13 वें राष्ट्रपति बनने मैदान में उतरे। 13 नंबर का बंगला है दिल्ली में। 13 तारीख को आती है शादी की सालगिरह। 13 जून को ही ममता ने प्रणब का नाम उछाला था।

तुम इसी लाइफ में बनोगे राष्ट्रपतिः जब 1969 में प्रणब राज्यसभा के सदस्य बने तो उनका आधिकारिक घर राष्ट्रपति संपदा के पास ही था। राष्ट्रपति भवन के ठाठ को प्रणब खूब निहारा करते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति की घोड़े वाली बग्गी को देखकर अपनी बहन अन्नापूर्णा बनर्जी से कहा कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का आनंद उठाने के लिए वो अगले जन्म में घोड़ा बनना पसंद करेंगे, लेकिन तब उनकी बहन ने उन्हें कहा था कि इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में तुम्हें इसमें रहने रहने का मौका मिलेगा।

बचपन से ही थे जिद्दीः प्रणब मुखर्जी के जो तेवर आज दिखते हैं वही तेवर आज बचपन में भी दिखते थे। अपनी जिद्द के चलते उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान डबल प्रोमोशन पाया। दरअसल दूसरी कक्षा में उन्होंने अपने परिवार वालों से मिराती गांव के स्कूल जाने से इंकार कर दिया। वह किरनाहर स्थित स्कूल में प्रवेश पाना चाहते थे। किरनाहर स्थित स्कूल पांचवी कक्षा से था। ऐसे में प्रणब ने किरनाहर के स्कूल में सीधे पांचवीं कक्षा में प्रवेश पाने के टेस्ट दिया और उसे पास भी करके दिखाया।

वीरभूम से दो देशों के राष्ट्रपतिः प्रणब के राष्ट्रपति बनने पर वीरभूम का नाम ऐसे जिलों में शुमार हो गया, जहां से दो देशों के राष्ट्रपति संबंध रखते हैं। प्रणब से पहले इसी जिले में जन्मे अब्दुल सत्तर (दकर गांव में जन्मे) 1981 से 1982 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। असल में वह विभाजन के बाद ढाका चले गए थे।

न्यूज

कानपुर में बिकरू कांड का आरोपी गिरफ्तार

कानपुर, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में क्षेत्राधिकारी समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में नामदज और 50 हजार के इनामी बदमाश रावेंद्र कुमार उर्फ रविंद्र कुमार उर्फ रामू वाजपेयी को पुलिस की टीम ने बिकरू रोड़ पर से गिरफ्तार किया है। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में गत दो-तीन जुलाई की मध्य रात्रि हुए बिकरू कांड को अंजाम देने के बाद से लगातार फरार चल रहे हैं, आखिरी इनामी आरोपी को पुलिस ने रामू वाजपेयी गिरफ्तार कर लिया है।

रेडक्रास खरीदेगा साढ़े दस लाख खादी मास्क

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को 10.5 लाख खादी मास्क खरीदने का आर्डर दिया है। आयोग ने सोमवार को यहां बताया कि रेडक्रास ने एक महीने के भीतर यह दूसरा आर्डर दिया है। इससे पहले रेडक्रास ने 1.80 लाख मास्क खरीदे थे। आयोग के अध्यक्ष वीके सक्सेना ने बताया कि साढ़े दस लाख मास्क की कीमत तकरीबन 3.30 करोड़ होगी। इसकी आपूर्ति एक सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जाएगी।

पतंग के साथ 100 फीट हवा में उछली 3 साल की लड़की

ताइपे, (एजेंसी)। ताइवान में पतंग उत्सव के दौरान एक तीन साल की लड़की हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। दरअसल पतंग को उड़ाने के दौरान उसकी एक डोर बच्ची से लिपट गई और वह हवा में 100 फीट तक उछल गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह लड़की को बचा लिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना को देख वहां मौजूद लोग भी सहम गए। इस दौरान वह छोटी लड़की हवा में 30 सेकंड के आसपास रही।

डॉ. अजय चौटाला जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए

पंचकूला, (एजेंसी)। जननायक जनता पार्टी(जजपा) संस्थापक और पूर्व सांसद डॉ. अजय सिंह चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को यहां हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। बैठक में डॉ. अजय सिंह चौटाला स्वयं भी उपस्थित थे। श्री चौटाला ने बैठक के बाद स्वयं ट्वीट कर पार्टी के इस फैसले की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का इसके लिए आभार व्यक्त किया।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

बलूचिस्तान में दमनकारी शासन के विरोध में पाक के खिलाफ यूके संसद के बाहर प्रदर्शन

नई दिल्ली ■ एजेंसी

बलूच फोरस के सदस्यों ने की पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी

विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिस्पीयरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले। यूके की संसद और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास के बाहर सिंधी बलूच फोरम और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने बलूचिस्तान में हो रहे दमनकारी शासन को लेकर पाक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिंधी बलूच फोरम के सदस्य हाथ में पाक सरकार के विरोध के पोस्टर लिए हुए यूके की संसद के बाहर खड़े हुए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया। वहीं दूसरी ओर फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के सदस्यों ने लंदन में स्थित यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास का घेराव किया। समूह के सदस्यों ने बलूच नागरिकों की हो रही हत्याओं को रोकें जैसे पोस्टरों के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया।

पाक का समर्थन करने से रोकने का आग्रह

उन्होंने ब्रिटेन सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान का समर्थन करने से रोकने का आग्रह किया, क्योंकि उनका समर्थन पाकिस्तान को मानवता के खिलाफ अधिक अपराध करने की अनुमति दे रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हजारों निर्दोष बलूच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाद में वे गायब हो गए हैं। उनमें से कई हिरासत में मारे गए हैं। उन्होंने हयात बलूच की हालिया हत्या की भी कड़ी निंदा की, जिसे फ्रंटियर कोर द्वारा उनके माता-पिता के सामने बलूचिस्तान के तुर्बत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

कोरोना की चुनौती से निबटने पर हुए सर्वे में खुलासा

महामारी को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन का प्रदर्शन खराब

वाशिंगटन ■ एजेंसी

कोरोना वायरस से निबटने में ब्रिटेन और अमेरिका का खराब प्रदर्शन रहा है। एक सर्वे में बताया गया है कि अन्य विकसित देशों की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप और बोरिस जॉनसन की सरकार ने महामारी का ठीक ढंग से सामना नहीं किया। 46 फीसद ब्रिटेन वासी और 47 फीसद अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि उनकी सरकार ने महामारी का सामना ठीक तरीके से किया। उसके मुकाबले 95 फीसद डेनमार्क के लोगों ने अपनी सरकार की चुनौती का सामना अच्छे तरीके से करने पर प्रशंसा की।

लॉकडाउन नहीं लगाने के बावजूद 71 फीसद डेनमार्क के लोगों ने सरकार के विवादास्पद दृष्टिकोण को सराहा। वाशिंगटन के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में ये बात सामने आई है। उसने 14 विकसित देशों के 14 हजार नागरिकों का इंटरव्यू कर सर्वे रिपोर्ट तैयार की। जिन लोगों ने सरकार के पक्ष में भरोसा जताया उनकी तादाद सरकार के ठीक तरीके से न संभाल पाने के आलोचकों की तुलना में ज्यादा थी। सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा देशों के लोगों ने महामारी से निबटने में सरकार के प्रयास को अच्छा बताया। सिर्फ 27 फीसद लोगों ने कहा कि उनकी सरकार ने महामारी का मुकाबला खराब तरीके से किया।

कोविड से निबटने में विकसित देशों की भूमिका पर सवाल

खराब हो चुकी अर्थव्यवस्था वाले सभी देशों के लोगों ने नकारात्मक राय दी। लॉकडाउन के कारण मंदी की चपेट में आ चुके ब्रिटेन के लोगों ने भी महामारी से निबटने के लिए सरकार के तरीके को ठीक नहीं माना। शोधकर्ताओं ने 10 जून और 3 अगस्त के बीच लोगों की राय टेलीफोन पर ली। उन्होंने सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदलैंड्स, स्पैन, स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल किया। नागरिकों से कोविड-19 की समस्या से निबटने में सरकार की भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए थे।

सर्वे में बताया गया ब्रिटेन और अमेरिका का खराब प्रदर्शन

सर्वे में शामिल हर दस में से छह अमेरिकी ने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों को कम किया जा सकता था। उन्होंने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के महामारी के प्रति उदासीन रवैए को जिम्मेदार ठहराया। शोधकर्ताओं के मुताबिक डाटा से लोगों के राजनीतिक झुकाव का भी पता चलता है। अमेरिका और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लोगों का सियासी ध्रुवीकरण सामने आया।

55 फीसद ब्रिटेन के लोगों ने दी पॉजिटिव रेटिंग

दक्षिणपंथी रुजहान रखनेवाले 55 फीसद ब्रिटेन के लोगों ने बोरिस जॉनसन की कंजरवेटिव सरकार को पॉजिटिव रेटिंग दी। जबकि वामपंथी रुजहान रखनेवाले 26 फीसद नागरिकों के भी दक्षिणपंथियों जैसे विचार थे। उसी तरह अमेरिका में 76 फीसद रिपब्लिकन या रिपब्लिकन समर्थकों ने ट्रंप प्रशासन के बारे में कहा कि उसने चुनौती का अच्छे से मुकाबला किया। एक तिहाई डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के हामियों ने सरकारी प्रयास का समर्थन किया। ग्लासगो के राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन कर्टाइस ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सवाल कर रहे हैं।

आगरा में मां-बाप एवं इकलौते बेटे की नृशंस हत्या

घर के अंदर ही शवों को जलाने की कोशिश

आगरा, (एजेंसी)। आगरा जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह तीनों के शव जली अवस्था में घर के अंदर मिले। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद शवों को जलाने का प्रयास किया गया । मरने वालों में पति, पत्नी और जवान बेटा शामिल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

घटना थाना एत्माद्दौला के नगला किशनलाल की है। मृतकों में रामवीर (55 साल), उनकी पत्नी मीरा और 22 वर्षीय बेटा बबलू हैं। रामवीर मकान में परचून की दुकान चलाते थे। रविवार को वे ससुराल से लौटे थे। सोमवार सुबह साढ़े छह बजे पड़ोस के लोग उनकी दुकान से सामान लेने आए। दुकान बंद मिली। उन्होंने आवाज लगाई, किंतु घर से कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने घर के अंदर झांका तो धुआं निकल रहा था। अनहोनी की आशंका पर पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

श्रद्धांजलि

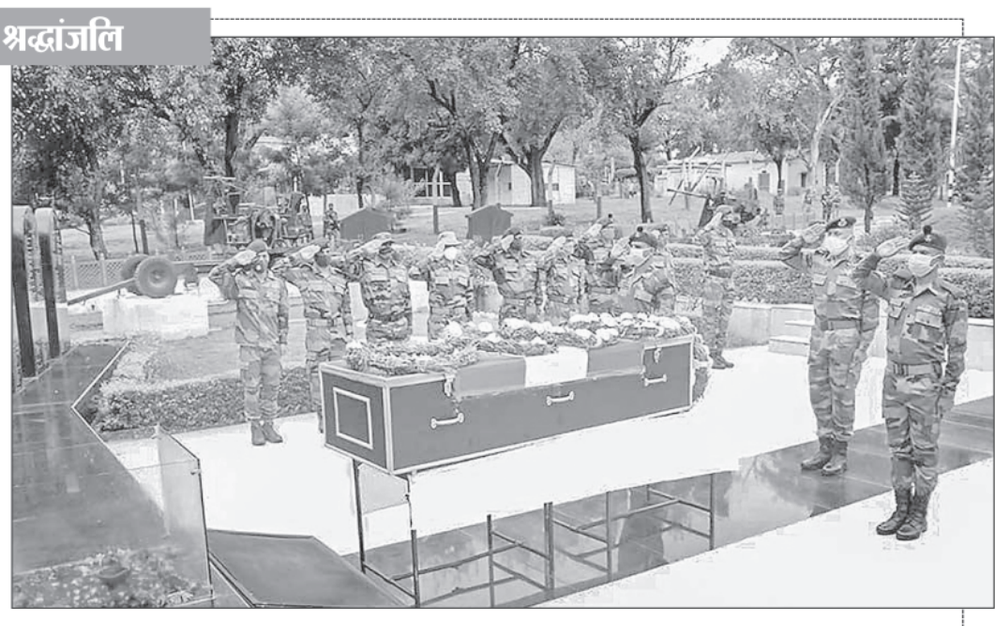

सुरक्षाकर्मियों ने राजौरी जिले में सोमवार को अपने माल्यार्पण समारोह के दौरान रविवार सुबह नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए नायब सूबेदार राजविंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मेहुल चोकसी और नाइक ने राजीव गांधी ट्रस्ट को दिए लाखों रुपए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा ने कांग्रेस और भगोड़े इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक के बीच कनेक्शन होने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि नाइक ने राजीव गांधी ट्रस्ट को 8 जुलाई 2011 को 50 लाख का चेक दिया था। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों का चूना लगाने वाले मेहुल चोकसी ने भी ट्रस्ट को 10 लाख दिए थे।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में शामिल है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के फाउंडेशन से मिले हैं। मेहुल के नाम पर गीतांजलि ग्रुप है। इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है मैसर्स नवीराज एस्टेट्स। इसने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के जरिए 10 लाख दान किए। वहीं नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ), मैसर्स हारमोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से ट्रस्ट को पैसा दिया गया। उसने 50 करोड़ 2012 से 2016 के बीच दिए। वहीं आईआरएफ ने 64.86 और 75 करोड़ 2003-04 और 2016-17 के बीच दिए। इसकी पीएमएलए के तहत जांच की जा रही है। इससे कांग्रेस को पैसा दिया गया। नाइक ने आरजीएफ को दान डीसीबी बैंक में खाता संख्या - 00120200000126 में किया था। यह खाता संख्या पीएमएलए के तहत जब्त किया गया है।

भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप

बाजपेई ने लड़खड़ाते कदमों से दी पत्नी और बेटे को मुखाग्नि

लखनऊ, (एजेंसी)। हमेशा मुस्कुराने वाले राजेश दत्त बाजपेई के आंसू रुक नहीं रहे थे। कभी पत्नी के शव देखते तो कभी बेटे का। आंखों का बांध टूट पड़ता और आंसू गालों पर लुढ़क आते। शायद उन्होंने खुद को इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया होगा। बोलने का प्रयास करते तो आवाज गले में घुट जाती।

बमुश्किल खुद पर काबू रखकर बेटी को संभालने में जुट जाते। दोपहर को बैकुंठधाम पर जब पत्नी और बेटे से विदाई के पल आए तो उनके कदम लड़खड़ा गए। पहले बेटे फिर पत्नी की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। रेलवे अधिकारी की पत्नी मालिनी और बेटे सर्वदत्त के शवों पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिए। दोपहर 12.30 बजे शव गौतमपल्ली में रेलवे अधिकारी के आवास पहुंचे तो कोहराम मच गया। परिवार की महिलाएं मां-बेटे के शव से चिपटकर रोने लगीं। साढ़े तीन बजे एंबुलेंस से दोनों शव बैकुंठधाम ले जाए गए, जहां रेलवे अधिकारी ने पहले बेटे और फिर पत्नी की चिता को मुखाग्नि दी।

3.5 करोड़ में बिकी दुनिया की सबसे महंगी भेड़

लनामार्क, (एजेंसी)। एक भेड़ की कीमत कितनी सोच सकते हो आप? ज्यादा से ज्यादा लाख-दो लाख, लेकिन करोड़ों पर बात पहुंच गई। स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ बिकी है 3.5 करोड़ रुपए की। ये दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है।

स्कॉटलैंड के लनामार्क में स्कॉटिश नेशनल टेक्सल सेल में गुरुवार को इस भेड़ को बेचा गया। इसकी नीलामी की गई। शुरुआत हुई 10,500 डॉलर से। धीरे -धीरे बढ़ते हुए लोगों के बीच में होड़ लग गई। फिर ये भेड़ बिकी 490,651 डॉलर में, भारतीय करेंसी के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपए। ये भेड़ डबल डायमंड के नाम से जाना जाती हैं।

आनंद शर्मा ने खोला मुंह, बोले-कार्यसमिति में जो कुछ हुआ उससे बहुत दुखी हूं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पार्टी के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ, उससे वो बहुत दुखी हैं। शर्मा ने कहा कि कार्यसमिति कि बैठक में ऐसे लोगों ने टिप्पणियां की, जिन्होंने चिट्ठी पढ़ी तक नहीं थी। ऐसे लोगों को हम पर बयान देने कि अनुमति दी गई।

आनंद शर्मा ने बातचीत में कहा कि हम में से कोई अध्यक्ष पद का दावेदार नही। चिट्ठी को लेकर कोई दुर्भावना न हो, इसलिए उन्होंने कार्यसमिति की बैठक में ही मांग की थी कि चिट्ठी को उसी वक्त मीडिया को रिलीज किया जाए, जिससे सबको पता चले कि चिट्ठी में पार्टी कि मजबूती के लिए सकारात्मक सलाह दी गई है। चिट्ठी में भाजपा पर सवाल उठाया गया है न कि गांधी परिवार को कोई चुनौती दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शर्मा ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक जानबूझकर उस प्रकार बुलाई गई थी और चिट्ठी के कुछ अंश को कुछ लोग जानबूझकर कर तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे थे।

'वन निगम में प्रमोशन घोटाले' संबंधी प्रकाशित खबर झूठी, तथ्यों से रहित और आधारहीन-साधु सिंह धर्मसोत

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के वन मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने 'वन निगम में प्रमोशन घोटाले' संबंधी मीडिया में आई खबर को झूठी, तथ्यों से रहित और आधारहीन बताते हुए खबर का खंडन किया है। आज यहाँ से जारी एक प्रैस बयान के द्वारा स. धर्मसोत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वह वन निगम की तरक्कियाँ नहीं करते। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरैक्टर की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के स्तर पर की जाती है और वन निगम में प्रोजैक्ट अफ्सर और निचले स्टाफकी प्रमोशन और बदलियों के लिए मैनेजिंग डायरैक्टर वन निगम समर्थ अधिकारी हैं।

स. धर्मसोत ने कहा कि मैनेजिंग डायरैक्टर की तरफसे वन निगम के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपने स्तर पर केवल योग्य कर्मचारियों की प्रमोशन और बदलियां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि वन निगम की तरक्कियों में वन मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि वन निगम के चेयरमैन श्री साधु सिंह संधू जी हैं, जबकि खबर में साधु सिंह धर्मसोत वन मंत्री लिखा गया है। जिक्रयोग्य है कि वन निगम में पिछले 4 सालों से प्रोजैक्ट अफ्सर और डिप्टी प्रोजैक्ट अफ्सर की कोई प्रमोशन नहीं हुई थी। काफी समय से वन निगम में प्रोजैक्ट अफ्सरों और डिप्टी प्रोजैक्ट अफ्सरों के खाली पड़े पदों से इन कर्मचारियों से अस्थायी तौर पर काम लिया जा रहा था। प्रोजैक्ट अफ्सर और डिप्टी प्रोजैक्ट अफ्सर को प्रमोट करने संबंधी कार्यवाही विभागीय तरक्की समिति के पास लगभग जून 2020 से विचाराधीन थी। विभागीय तरक्की समिति की तरफसे प्रोजैक्ट अफ्सरों का रिकॉर्ड विचारा गया है और तरक्कियों का फैसला भी विभागीय तरक्की समिति की तरफसे ही किया गया है।

शिरोमणि अकाली दल पंजाब अनुसूचित जाति के वाईस प्रधान सुभाष सौंधी ने मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया और साथ ही धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की। छाया: रवि

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली पंजाबी महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर को पंजाब सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का चैक भेंट

खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने खिलाड़ी की माता को दिया चैक

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के खेल और युवक मामले मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने आज ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली पंजाबी महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर को पंजाब सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का चैक लुधियाना में सिमरनजीत कौर की माता श्रीमती राजपाल कौर को भेंट किया। बताने योग्य है कि पिछले समय के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मुक्केबाज सिमरनजीत कौर को अपने कार्यालय में विशेष तौर पर बुलाया था और उसे पंजाब सरकार से पाँच लाख रुपए देने का ऐलान किया था। राणा गुरमीत सिंह सोढी ने बताया कि सिमरनजीत कौर ओलंपिक खेल के लिए क्वालीफाई होने वाली पहली पंजाबी महिला मुक्केबाज है। उन्होंने खिलाड़ी की माता को मुबारकबाद देते हुए कहा कि न सिर्फपंजाब बल्कि देश को उस पर गर्व है जिसने एशिया ओशेनिया क्वालीफाई मुकाबले में रजत पदक जीतकर दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच में उपस्थिति दर्ज करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह मुक्केबाज पंजाब की उन लड़कियों के लिए भी एक मिसाल है, जो मुक्केबाजी के खेल में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि साधारण परिवार की बेटी की यह आसाधारण प्राप्ति है और उसे आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद मुहैया करवाई जायेगी।

राणा सोढी ने सिमरनजीत कौर की ओलंपिक की तैयारी का समूचा खर्चा पंजाब सरकार द्वारा उठाने का भी ऐलान किया।

उन्होंने बताया कि लुधियाना जिले के गाँव चकर की इस मुक्केबाज ने गाँव से ही अपना करियर बनाना शुरू किया। 2013 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में काँस्य पदक, 2018में सीनियर विश्व चैंपियनशिप में काँस्य पदक और 2019 में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीते। मोहाली स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफस्पोर्टस में भी इस मुक्केबाज ने तैयारी की। मौजूदा समय में यह खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी में व्यस्त है।

इस मौके पर सिमरनजीत कौर की माता राजपाल कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह और पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए भरोसा दिया कि सिमरनजीत कौर कड़ी मेहनत और पंजाब सरकार के सहयोग से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगी और पंजाब का नाम रौशन करेगी।

मेहनती और कर्मठ अफसर हरमेश लाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जालंधर नगर निगम से हुए सेवा मुक्त

■ जालंधर/रवि

नगर-निगम जालंधर में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरमेश लाल आज सेवा मुक्त हो गए। उनकी गिनती बहुत ही सूझवान अफसरों में से एक थी। उनके कार्यकाल में हमेशा चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में इनको भेजा जाता था जो मसले काफी पुराने लंबित होते थे जैसे की लोगों की रोजमर्रा की गंदे पानी की समस्या को इन्होंने कई इलाकों में जड़ से खत्म किया। इसी कार्यशैली के कारण किसी भी सरकार के विधायक के चेहते ही रहे आज उनको साथी अफसरों ने परिवार वालों की मौजूदगी में सम्मानित किया और उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की कामना की और इस मौके पर निगम के मेयर जगदीश राजा, कमिश्नर कर्नेश शर्मा ,सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सतिंदर महाजन, उमा महेश्वर सुपरिंटेंडेंट और इंजीनियरिंग शाखा के अन्य अफसर मौजूद थे ।

मेयर ने किया नगर निगम के ठेकेदारों को खुश

■ जालंधर/रवि

नगर-निगम के ठेकेदारों की विकास कार्यों की लंबित पड़ी मांग को मानते हुए उन्हें चेक बाँटे गए जिस पर ठेकेदारों द्वारा खुशी का प्रगटावा करते हुए मेयर राजा और निगम कमिश्नर का धन्यवाद किया पिछले कई वर्षो बाद मेयर द्वारा बनती पूरी ठेकेदारों की धनराशि की अदायगी की गयी जो की तकरीबन ओ.एंड.म. और बी. एंड आर शाखा को मिलाकर 9.58 करोड़ बनती थी यह एक ठेकेदारों के लिए किसी इतिहासिक दिन से कम नहीं है।

नगर-निगम मेयर राजा द्वारा विकास कार्यों को दी नयी उड़ान

■ जालंधर/रवि

पिछले लंबे समय से चली आ रही दशमेश नगर, काकी पिंड और गुरु नानक पूरा रोड के लोगों की मांग को पूरा करते हुए आज नगर-निगम के मेयर और विधायक राजिंदर बेरी ने सड़कों के कार्यों के उद्घाटन किये जिसमे दशमेश नगर का खर्चा कुल 52.18 लाख,काकी पिंड का खर्चा 22.39 लाख आएगा और गुरु नानक पूरा रोड को दुबारा से लुक डाल कर नवीनीकरण किया जायेगा। इस मौके पर मेयर जगदीश राजा, विधायक राजिंदर बेरी,बी एंड आर सब समिति के चेयरमैन जगदीश गग,पार्षद गुरविंदरपाल सिंह बंटी और इलाकावासी मौजूद थे ।

चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हों परेशान, महेंद्र सिंह धोनी सब कुछ संभाल लेंगे

दुबई। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी और मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना आखिर वापस क्यों लौटे ? यह सवाल अभी भी सवालों के घेरे में है। हालांकि, क्रिकेटप्रेमियों के लिए यह खबर पुरानी हो गई कि सुरेश रैना वापस लौट आए हैं। लेकिन उनके पीछे की प्रतिक्रिया हर कोई जानना चाहता है और यह भी जानना चाहता है कि इस स्थिति में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम को कैसे संभालेंगे ? इस तरह से सवाल भी उठ रहे हैं।

सुरेश रैना के स्वदेश लौटने को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहली तो यह कि वो ताज दुबई में मिले अपने कमरे से खुश नहीं थे। जिसकी वजह से उनकी बहस टीम के सीईओ काशी विश्वनाथ से हो गई। जबकि उनके एक करीबी ने बताया कि वह अपने परिवार को काफी मिस कर रहे थे और इसी बीच टीम के 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिसकी वजह से उनके मन में कोरोना को लेकर डर बैठ गया। जिसके बाद रैना ने इस लीग से खुद को अलग करने का फैसला लिया। हालांकि, सत्य क्या है यह तो खुद सुरेश रैना और टीम मैनेजमेंट से ही पता चल सकेगा।

हालांकि, इसी बीच दुबई जाने से पहले रैना की बुआ के घर जो हमला हुआ था उसको लेकर उन्होंने बयान जारी किया है। रैना ने कहा कि पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो हुआ वह भयावह यह जानने का हकदार हूं कि यह किसने किया।

रैना पर भड़के चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक

सुरेश रैना के स्वदेश लौट जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन का बयान सामने आया। जिसमें उन्होने कहा था कि 11 करोड़ रुपए की राशि से सुरेश रैना हाथ धो बैठेंगे। मुझे लगता है कि वह लौट आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रैना जब से दुबई पहुंचे हैं तब से वह अलग-अलग बातों के लिए शिकायत करते रहे। उन्होंने कहा कि सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और रैना को समझ में आएगा कि वो क्या खो रहे हैं और पैसा जिससे वो हाथ धो बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कामयाबी रैना के सिर चढ़कर बोल रही है और इसीलिए वह तुनकमिजाज हो गए हैं।चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक श्रीनिवासन की बातों से तो यही लगता है कि सुरेश रैना नाखुश थे तभी वह दुबई में खेले जाने वाले आईपीएल को छोड़कर वापस भारत लौट आए।

गलत अर्थों में पेश किया गया बयान

श्रीनिवासन का बयान चारों तरफ छाया रहा। जिसमें उन्होंने कहा कि कामयाबी रैना के सिर चढ़कर बोल रही है और इसीलिए वह तुनकमिजाज हो गए हैं। इस बयान के सुर्खियां बटोरने के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में श्रीनिवासन ने कहा कि मेरे बयान को गलत अर्थों में पेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स में रैना का योगदान किसी से भी नंबर दो नहीं है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग बयान का गलत मतलब निकाल रहे हैं।

परेशान न हों चेन्नई फैन्स

गेंदबाज दीपक चाहर समेत 13 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से और सुरेश रैना के स्वदेश लौट जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के फैन काफी परेशान हो गए थे लेकिन उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बोला है कि वह सबकुछ संभाल लेंगे।

श्रीनिवासन ने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी ने मुझे आश्वासन दिलाया है चाहे नंबर ज्यादा क्यू न हो जाए वह सब कुछ संभाल लेंगे। इसके अतिरिक्त सीएसके फैन्स के लिए एक राहत की खबर भी है। टीम के अनुभवी बल्लबाजों में से एक फॉक डुप्लेसिस टीम से जुड़ चुके हैं और उनके साथ लुंगी एनगिडी भी देखे गए हैं।

धर्मसोत को बर्खास्त करने के बजाए 'क्लीन चिट' देने के लिए उतावले है मुख्यमंत्री- हरपाल सिंह चीमा

■ जालंधर/रवि

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने दलित विद्यार्थियों की बहुकरोड़ी घोटाले में घिरे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को तुरंत बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के विरुद्ध सोमवार को जालंधर से राज्यस्तरीय मोर्चा शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा और विधायकों प्रो. बलजिंदर कौर रतन सिंह करकरकला, जोगिंदरपाल शर्मा, रोशन लाल मौजूद थे। इस मौके मीडिया को संबोधन करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत लाखों होनहार दलित छात्राओं के भविष्य का हत्यारा है। दलित छात्राओं की वजीफा राशि में से सीधा 63.91 करोड़ रुपए हड़पने वाले मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ अडिशनल मुख्य सचिव

के नेतृत्व में 'आप' लीडरशिप ने पहले डिप्टी कमिशनर के कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। सरकार के विरुध नारेबाजी की और मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह और मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के पूतले फूके।

इस रोष प्रदर्शन के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कालर्शिप (वजीफा) स्कीम से वंचित रही दलित परिवारों से संबंधित 5 छात्राओं को साथ लेकर 'आप' लीडरशिप ने डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी द्वारा पंजाब के राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। इस मौके उनके साथ डा. शिव दयाल माली, डा. संजीव शर्मा, हरजिंदर सिंह सीचेवाल, दर्शन सिंह भगत, राजविंदर कौर, गुरिंदर सिंह शेरगील, द्वारा जितने दस्तावेजी सबूतों के साथ सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसकी गंभीरता को देखते हुए इस भ्रष्ट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को 5 मिनटों में मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके फौजदारी मुकद्दमा दर्ज कर लिया जाना चाहिए था ताकि अबतक मंत्री और उसका पूरा भ्रष्ट गिरोह गिरफ्तार कर लिया जाता, परंतु राजा अमरिन्दर सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करने के बजाए उसको 'क्लीन चिट' की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।

इस कारण एक सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी की जांच पर भरोसा न करके जांच दूसरे सीनियर आई.ए.एस. (मुख्य सचिव) को सौंप दी है। चीमा ने आरोप लगाया कि जिस जल्दबाजी और शिद्दत के साथ मुख्यमंत्री एक भ्रष्ट मंत्री की पीठ पर खड़े हो गए है, उससे सीधा प्रभाव जाता है कि दलित छात्राओं के वजीफे की हड़पी गई राशि का हिस्सा मुख्यमंत्री के 'फारम हाऊस' तक पहुंचता है। उन्होंने पूरे वजीफा घोटाले की जांच माननीय हाईकोर्ट के मौजूदा जजों की निगरानी में सी.बी.आई. या किसी भी केंद्रीय एजैंसी से करवाने की मांग की। 'आप' नेताओं ने यह भी मांग की है कि दलित छात्राओं के लिए केंद्र की इस पोस्ट मैट्रिक स्कालर्शिप स्कीम में हुए घोटालों की जांच का दायरा वर्ष 2012-13 तक बढ़ाया जाए क्योंकि पूर्व अकाली भाजपा सरकार के समय भी इस स्कीम में 1200 करोड़ से अधीक रुपए की गड़बड़ी हुई है।

'आप' नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस ने धर्मसोत को बर्खास्त न किया तो लोगों के सहयोग से 'आप' पूरे पंजाब में रोष प्रदर्शन करेगी, जिसकी शुरूआत आज दोआबा की सरकामी से कर दी गई है।

पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ 52.82 लाख का जुर्माना लगाया

■ जालंधर/रवि

पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारीयों ने बिजली चोरी करने वालो के खिलाफ कारवाई करते हुए उन पर 52.82 लाख का जुर्माना लगाया। मुख्य इंजीनियर जैन इन्दर दानिया उत्तरी जोन जालंधर की तर? से दी गई हिदायतों के अनुसार 29-08-2020 को जालंधर,होशियारपुर,नवांशहर और कपूरथला के इलाकों में उप मुख्य इंजीनियर हरजिंदर सिंह बांसल, इंजीनियर इंदरपाल सिंह, इंजीनियर पी एस खाम्बा और इंजीनियर देसराज बंगड़ की देख रेख में छापेमरी की गई। इस छापेमारी दौरान जालंधर में आते इलाको में 1654 केस चेक किये गए जिस में 47 बिजली चोरी के, 30 केस बिजली के ओवर लोड और 5 केस यू.यू.इ. के थे जिनसे 15.78 लाख की राशि जुर्माना बिजली चोरी करने वालो पर लगाया। इसी तरह कपूरथला के इलाको में भी 1930 की चेकिंग की जिस में 67 केस बिजली चोरी के, 28 केस ओवर लोड के और 22 केस यू.यू.इ. के सामने आए जिसमें 16.33 लाख का जुर्माना लगाया और इसी तरह होशियारपुर में भी बिजली चोरी करने वालो पर छापेमरी दौरान 2142 केस सामने आए जिसमे 15 केस बिजली चोरी के 153 केस ओवर लोड और 18 केस यू.यू.इ के नज़र आए जिसमे कुल राशि 12.43 लाख का जुर्माना लगाया। नवांशहर में भी बिजली की चोरी के 787 केस सामने आए जिसमें 18 केस चोरी की गई बिजली के और 50 ओवर लोड के थे इनको भी कुल राशि 8.28 लाख जुर्माना लगाया। बिजली चोरी के मामलों में करदाताओं के ऊपर बिजली एक्ट 2003 के अंतर्गत सेक्शन 135 अधीन अलग अलग पुलिस डिवीज़न में मामला दर्ज भी करवाया जा रहा है। मुख्य इंजीनियर जैन इन्दर दानिया की तरफ से अपील की जाती है की बिजली चोरी करना एक समाजिक अपराध है यदि इसकी जानकारी हमें कोई देता है उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्होंने ने लोगों से अपील की जिन लोगों के बिल पेंडिंग है वह अपने बिल जल्द से जल्द जमा करवाए ।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.